

CORPORATE KALEIDOSCOPE

GAIL (India) Limited and the Central Board of Direct Taxes (CBDT) entered into the Advance Pricing Agreement (APA) for determining the Transfer Pricing Margin payable on its long-term LNG sourcing contract from USA for the period of five years from 2017-2022. The APA Scheme enhances the Central Government's goal of promoting a non-adversarial tax system and improve the ease of doing business in India. GAIL is the first PSU, successfully signed the APA in Oil & Gas sector in India. The APA was signed by Joint Secretary, FT & TR-1, CBDT Rasmi Ranjan Das and R K Jain, Director(Finance) GAIL(India) Limited.

MPOST



GAIL a Partner organisation of the prestigious India Energy Week being held in Bengaluru from 6th to 8th Dec., 2023, is showcasing its commitment towards a Cleaner and Greener Future at the exhibition being held on the occasion. The India Energy Week, being organized under the patronage of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, is the first major event under India's G20 Presidency. The theme of the GAIL stall at the IEW exhibition, 'Energizing a Sustainable Future', is an affirmation of the Company's Mission Statement - "Enhancing quality of life through clean energy and beyond."



GAIL a Partner organisation of the prestigious India Energy Week being held in Bengaluru from 6th to 8th Dec., 2023, is showcasing its commitment towards a Cleaner and Greener Future at the exhibition being held on the occasion. The India Energy Week, being organized under the patronage of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, is the first major event under India's G20 Presidency. The theme of the GAIL stall at the IEW exhibition, 'Energizing a Sustainable Future', is an affirmation of the Company's Mission Statement - "Enhancing quality of life through clean energy and beyond."



GAIL signs advance pricing agreement with the CBDT

New Delhi: GAIL and the Central Board of Direct Taxes (CBDT) on Thursday entered into a landmark advance pricing agreement (APA) for determining the transfer pricing margin payable on its long-term LNG sourcing contract from the US for a period of five years. The APA scheme enhances the government's goal of promoting a non-adversarial tax system and improving ease of doing business in India. GAIL is the first PSU in oil & gas sector in India to successfully sign the APA.

SAURAV ANAND



GAIL signs advance pricing agreement with the CBDT

New Delhi: GAIL and the Central Board of Direct Taxes (CBDT) on Thursday entered into a landmark advance pricing agreement (APA) for determining the transfer pricing margin payable on its long-term LNG sourcing contract from the US for a period of five years. The APA scheme enhances the government's goal of promoting a non-adversarial tax system and improving ease of doing business in India. GAIL is the first PSU in oil & gas sector in India to successfully sign the APA.

SAURAV ANAND

ऊर्जा बदलाव को देख कंपनियां बदलने लगी रणनीति

ओएनजीसी, आइओसी और गेल तैयार कर रही हैं भावी नीति, एनटीपीसी भी बदलने लगी है प्रकृति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : ऊर्जा सेक्टर के दिग्गज अंबानी और अदाणी समूह तो पहले ही ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट कर चुके हैं। अब सरकारी क्षेत्र की ओएनजीसी, आइओसी, एनटीपीसी, गेल जैसी दिग्गज कंपनियां भी मान रही हैं कि भविष्य में टिके रहने के लिए उन्हें परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से बाहर निकलना पकड़ेगा। इनमें से अधिकांश कंपनियों ने बेंगलुरु में बुधवार को समाप्त हुए इंडिया एनर्जी वीक (आइडब्लू) में अपनी भविष्य की झलक दी है। जैसे ओएनजीसी अगले दस वर्षों में आफशोर विंड एनर्जी से लेकर बायो-पथूल को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख कंपनी होगी। आइओसी और गेल भी रिनीवेबल ऊर्जा के कई सेक्टरों में विस्तार करने की रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हैं।

ओएनजीसी के सीएमडी अरुण कुमार सिंह का कहना, "ऊर्जा सेक्टर में जिस तेजी से बदलाव हो रहा है उस पर हमारी कंपनी की पूरी नजर है। देश को अभी लंबे समय तक



- ओएनजीसी के सीएमडी ने कहा, लंबे समय तक पारंपरिक ईंधन जैसे कच्चे तेल की जरूरत रहेगी
- आइओसी के मुताबिक, दूसरी कंपनियों के मुकाबले ग्रीन हाइड्रोजन में उसके लिए अपार संभावनाएं

पारंपरिक ईंधन जैसे कच्चे तेल की जरूरत रहेगी और पूरी तरह से हरित ईंधन को देशभर में अपनाने से पहले हम एक ऐसे दौर में होंगे, जिसमें कम प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों की

सौर और पवन ऊर्जा दो बड़े सेक्टर

देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी इंडियन आयल कार्पोरेशन (आइओसी) ने वर्ष 2046 तक नेट जीरो कंपनी (कार्बन उत्सर्जन नहीं करने वाली कंपनी) का लक्ष्य रखा है। कंपनी बहुत ही गंभीरता से ग्रीन एनर्जी के लिए अलग से सब्सिडियरी स्थापित करने पर विचार कर रही है। मुख्य तौर पर इसकी नजर हाल ही में घोषित ग्रीन हाइड्रोजन



श्रीकांत माधव वैद्य

नीति के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों (इवी) की चार्जिंग सुविधा के नेटवर्क में विस्तार की है। वैसे कंपनी सौर और पवन ऊर्जा सेक्टर में प्रवेश कर चुकी है लेकिन कंपनी प्रबंधन को लगता है कि ग्रीन हाइड्रोजन में उसके लिए अपार संभावनाएं होंगी। जबकि मौजूदा पेट्रोल पंप नेटवर्क की वजह से

मांग भी काफी ज्यादा होगी। बतौर देश की सबसे प्रमुख ऊर्जा कंपनी के तौर पर हमारी रणनीति इस पूरे परिवर्तन काल के लिए होगी।" इस बारे में ओएनजीसी की निदेशक

यह मान रही है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा देने में वह दूसरी कंपनियों के मुकाबले ज्यादा बेहतर स्थिति में है।

आइओसी के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य का कहना है कि सौर और पवन ऊर्जा दो बड़े सेक्टर हैं, जिसको लेकर हमारी कंपनी बहुत महत्वाकांक्षी योजना रखती है। इन दोनों सेक्टरों के लिए बायोगैस में हम बहुत संभावना देख रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है

कि हाइड्रोजन सेक्टर में भी आइओसी पूरे देश को एक नई दिशा दिखाएगी। दूसरी तेल मार्केटिंग कंपनियां भी ईवी को लेकर ज्यादा उत्साहित हैं। भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) दिल्ली-जालंधर हाइवे पर फास्ट चार्जिंग कारीडोर बनाने का एलान कर चुका है।

(एक्सप्लोरेशन) सुषमा रावत कहती हैं कि रिनीवेबल सेक्टर में हम अभी शुरुआती स्तर पर हैं लेकिन बहुत ही कम समय में हम सोलर और विंड में उतर चुके हैं। कार्बन कैप्चरिंग को

रिनीवेबल सेक्टर में अपने आप को ढालने में जुटी एनटीपीसी

देश की सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड सबसे तेजी से रिनीवेबल सेक्टर में अपने आप को ढालने में जुटी है। इसने वर्ष 2032 तक अपनी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 45 प्रतिशत रिनीवेबल सेक्टर से बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए कंपनी की तरफ से 2.5 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की संभावना है। सितंबर, 2022 में कार्बन कैप्टरिंग यूनिट शुरू कर चुकी एनटीपीसी इस स्रोत को लेकर काफी उत्साहित है।

लेकर हम बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं और इसके लिए आइओसी के साथ काम कर रहे हैं। आफशोर इलाकों में विंड पावर प्लांट लगाने पर भी हमारा फोकस है।

सीबीडीटी के साथ गेल का समझौता

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 9 फरवरी

सरकार द्वारा संचालित गेल (इंडिया) लिमिटेड ने गुरुवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट (एपीए) किया है। इससे अमेरिका से 5 साल की अवधि के लिए हुए उसके दीर्घावधि एलएनजी सोर्सिंग कांट्रैक्ट पर ट्रांसफर प्राइसिंग मुनाफे का निर्धारण होगा।

गेल तेल एवं गैस क्षेत्र की पहली सरकारी कंपनी है, जिसने एपीए पर हस्ताक्षर किया है। एपीए योजना 2022 में लाई गई थी। सरकार ने गैर प्रतिकूल कर प्रणाली को बढ़ावा देने और भारत में कारोबार सुगमता के मकसद से यह योजना पेश की थी।

आयकर विभाग के मुताबिक एपीए योजना कई देशों में लागू है और कनाडा, यूएसए और यूके में यह 30 साल पुरानी है। इस तरह की योजना का प्राथमिक मकसद करदाताओं को सीमा पार लेन-देन के मामलों में कर को लेकर निश्चितता प्रदान करना है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तेजी से बढ़ोतरी और बहुराष्ट्रीय उद्यमों की संख्या बढ़ने के कारण ट्रांसफर प्राइसिंग के मसले में कर संबंधी तमाम विवाद सामने आए हैं। एपीए एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें ट्रांसफर प्राइसिंग के मसले को पहले ही हल कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए सीमा पार लेन देन वास्तव में होने के पहले या कम से कम विवाद उठने के पहले इसे सुलझा लिया जाता है।